



पशुधन की उत्पादकता और लाभ में वृद्धि हेतु शासकीय योजनाओं का विश्लेषण: रायपुर (छत्तीसगढ़) के संदर्भ में एक अध्ययन

आशीष कुमार दुबे, पीएच-डी, रेणु कुमार यादव, शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
विवेकानंद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Authors

आशीष कुमार दुबे, पीएच-डी
रेणु कुमार यादव, शोधार्थी
E-mail : drashishdubey24@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 06/02/2026
Revised on : 09/04/2026
Accepted on : 18/04/2026
Overall Similarity : 00% on 10/04/2026



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

0%

Overall Similarity

Date: Apr 10, 2026 (07:28 AM)
Matches: 13 / 2833 words
Sources: 2

Remarks: No similarity found,
your document looks healthy.

Verify Report:
Scan this QR Code



शोध सार

भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र कृषि का पूरक एवं ग्रामीण आय का प्रमुख स्रोत है। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है, किंतु प्रति पशु उत्पादकता अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है। छत्तीसगढ़ राज्य, विशेषकर रायपुर जिला, पशुपालन आधारित आजीविका के विस्तार की दृष्टि से उभरता हुआ क्षेत्र है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय डेयरी योजना तथा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि ने उत्पादकता एवं लाभ वृद्धि के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान किया है। प्रस्तुत शोध में रायपुर जिले के संदर्भ में इन योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों, जिला पशुपालन कार्यालय रिपोर्टों तथा सहकारी दुग्ध संघों के अभिलेखों पर आधारित है। परिणामों से स्पष्ट है कि दुग्ध संकलन, कृत्रिम गर्भाधान, चारा विकास एवं प्रसंस्करण अवसंरचना में सुधार से आय में वृद्धि हुई है, किंतु तकनीकी प्रशिक्षण, विपणन एकीकरण तथा वित्तीय समावेशन में सुधार की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द

पशुधन उत्पादकता, रायपुर, छत्तीसगढ़, दुग्ध उत्पादन, सरकारी योजनाएँ, ग्रामीण आय.

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ कृषि के साथ-साथ पशुधन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। पशुधन केवल कृषि का पूरक नहीं है, बल्कि यह आय, रोजगार, पोषण सुरक्षा तथा सामाजिक स्थिरता का प्रमुख स्रोत भी है। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पशुपालन जोखिम कम करने वाला, नियमित नकद आय देने वाला तथा कम भूमि पर आधारित आजीविका का साधन है। पशुधन क्षेत्र में "उत्पादकता वृद्धि" और "लाभ वृद्धि" परस्पर संबंधित अवधारणाएँ हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने समय-समय पर पशुधन विकास को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक योजनाएँ

प्रारंभ की हैं। किसी भी योजना की सफलता का मूल्यांकन जिला स्तर पर करना अधिक यथार्थपरक माना जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य, जो वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया, प्राकृतिक संसाधनों एवं कृषि संभावनाओं से समृद्ध है। रायपुर जिला, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, प्रशासनिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। शहरी बाजार की निकटता, परिवहन सुविधाएँ तथा प्रसंस्करण इकाइयों की उपलब्धता इसे पशुधन उत्पादों के विपणन के लिए अनुकूल बनाती है। रायपुर जिले में पशुधन की उत्पादकता वृद्धि का सीधा प्रभाव ग्रामीण आय पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (CGCDF), रायपुर के अंतर्गत कार्य किया जाता है। दुग्ध संघ इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण उत्पादकों से दूध खरीदकर उसे "देवभोग" के रूप में संसाधित और विपणन करते हैं। हालाँकि सरकारी योजनाएँ व्यापक स्तर पर संचालित की जा रही हैं, किंतु उनके प्रभाव में क्षेत्रीय असमानता देखी जाती है। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य रायपुर (छत्तीसगढ़) के संदर्भ में पशुधन की उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि हेतु संचालित शासकीय योजनाओं का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि इन योजनाओं ने वास्तविक स्तर पर किस प्रकार परिवर्तन लाया है, और किन क्षेत्रों में अभी सुधार की आवश्यकता है। जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नीति निर्माण एवं ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी उपयोगी है। रायपुर जिले के संदर्भ में यह अध्ययन भविष्य की रणनीतियों के निर्धारण हेतु एक आधार प्रदान करता है और पशुधन क्षेत्र को आत्मनिर्भर एवं लाभकारी बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देता है।

साहित्य समीक्षा

सिंह, आर. (2015) ने अपने अध्ययन में रायपुर जिले के दुग्ध उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। शोध में यह पाया गया कि संकर गायों की उत्पादकता एवं लाभ अन्य पशुओं की तुलना में अधिक है। दुग्ध उत्पादन लागत में चारा व्यय का सर्वाधिक योगदान देखा गया। यह अध्ययन छोटे पशुपालकों की आर्थिक व्यवहार्यता एवं विपणन निर्णयों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।¹

दास, अर्धदीप एवं अन्य (2020) द्वारा किए गए अध्ययन में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र की भूमिका का व्यापक विश्लेषण किया गया है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि पशुपालन विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत प्रदान करता है तथा गरीबी उन्मूलन में सहायक है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि पशुधन क्षेत्र आय असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, पशुपालन से पोषण स्तर में सुधार तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पशुधन अपनाने पर सामाजिक-आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो इसके विकास की दिशा निर्धारित करते हैं।¹

मिश्रा, पी. एवं अन्य (2020) द्वारा किए गए अध्ययन में भारत एवं छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन की प्रवृत्तियों का सांख्यिकीय मॉडलिंग के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। शोध में ARIMA मॉडल का उपयोग कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि दुग्ध उत्पादन में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है। अध्ययन के अनुसार, भारत में दुग्ध उत्पादन में छोटे एवं सीमांत किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। पूर्वानुमान परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले वर्षों में दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभावित है। यह शोध पशुधन क्षेत्र की विकास संभावनाओं एवं नीति निर्माण के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है।²

सरकार, अनुपम (2020) ने अपने अध्ययन में अनुसूचित जाति (SC) कृषकों के लिए पशुपालन की आजीविका संबंधी संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। शोध से स्पष्ट होता है कि संसाधनों, भूमि एवं बाजार तक सीमित पहुंच के कारण ये वर्ग पशुधन क्षेत्र का पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहा है। अध्ययन यह निष्कर्ष देता है कि संरचनात्मक बाधाओं को दूर किए बिना पशुपालन को प्रभावी आय स्रोत बनाना कठिन है।³

गुलाटी अशोक एवं जुनेजा रितिका (2022) द्वारा किए गए अध्ययन में भारतीय कृषि के संरचनात्मक परिवर्तन और उसके विकास में नीतियों, निवेश एवं तकनीकी प्रगति की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। शोध यह संकेत देता है कि कृषि क्षेत्र ने उत्पादन एवं आत्मनिर्भरता के स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु भविष्य में स्थिरता एवं जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ बनी रहेंगी। अध्ययन निष्कर्षतः संतुलित एवं समावेशी कृषि नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है, जिससे दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।⁴

तिवारी, प्रज्ञा (2024) ने अपने अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ (देवभोग) की दुग्ध व्यवसाय के विकास में भूमिका का विश्लेषण किया गया है। शोध से स्पष्ट होता है कि इस संस्था ने किसानों को उचित मूल्य पर बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आय में सुधार किया है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि दुग्ध उद्योग, जो पहले सीमित ग्रामीण गतिविधि था, अब व्यावसायिक रूप में विकसित हो रहा है। हालांकि, देवभोग ब्रांड की उपयोगिता के बावजूद उपभोक्ताओं में इसकी जागरूकता अपेक्षाकृत कम पाई गई है। यह शोध दुग्ध क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के महत्व और उनके विस्तार की संभावनाओं को रेखांकित करता है।³

बर्द्धन डी. एवं अन्य (2025) के अध्ययन में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पशुधन जनसंख्या की प्रवृत्तियों एवं संरचना का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि दोनों राज्यों में विभिन्न पशु प्रजातियों की हिस्सेदारी में समय के साथ परिवर्तन हुआ है तथा ग्रामीण आजीविका में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। अध्ययन निष्कर्षतः पशु स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत संरचना एवं नीतिगत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देता है।⁷

अध्ययन के उद्देश्य

1. यपुर (छत्तीसगढ़) में पशुधन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. पशुधन उत्पादकता बढ़ाने हेतु संचालित प्रमुख शासकीय योजनाओं का अध्ययन करना।
3. योजनाओं के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. चुनौतियों एवं सुधारात्मक सुझावों की पहचान करना।

शोध पद्धति: इस अध्याय में प्रस्तुत अध्ययन की शोध पद्धति का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह शोध पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

1. **अध्ययन का क्षेत्र:** अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र रायपुर जिला (छत्तीसगढ़) है। जिला स्तर पर उपलब्ध पशुधन, दुग्ध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य सेवाओं एवं शासकीय योजनाओं से संबंधित आँकड़ों का संकलन किया गया है।
2. **समंक का स्रोत:** यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित है। डेटा निम्नलिखित स्रोतों से संकलित किया गया है:
 - (1) शासकीय प्रकाशन एवं प्रतिवेदन।
 - (2) राष्ट्रीय स्तर के स्रोत।
 - (3) शोध लेख एवं जर्नल।
 - (4) अन्य द्वितीयक स्रोत।

नैतिक विचार: अध्ययन में उपयोग किए गए सभी आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रकाशित स्रोतों से लिए गए हैं। किसी भी प्रकार के निजी या गोपनीय डेटा का उपयोग नहीं किया गया है। सभी स्रोतों का उचित संदर्भ अनुसंधान की पारदर्शिता एवं शैक्षणिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

समंकों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. **पशुधन संख्या में परिवर्तन का विश्लेषण:** द्वितीयक आँकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में रायपुर जिले में कुल पशुधन संख्या में हल्का लेकिन स्थिर परिवर्तन देखा गया है। पारंपरिक रूप से ग्रामीण परिवारों में गाय एवं भैंस पालन प्रमुख रहा है, किंतु समय के साथ बकरी एवं कुक्कट पालन की ओर भी रुझान बढ़ा है।

रायपुर जिले में पशुधन जनगणना

कुल पशुधन	20जी छत्तीसगढ़ पशु संगणना (2019)	19जी छत्तीसगढ़ पशु संगणना (2012)	18जी छत्तीसगढ़ पशु संगणना (2007)
गाय	343625	399983	425896
भैंस	62579	65884	68559
बकरी	70311	65951	55574
भेड़	8227	6617	7626
सुअर	1749	4095	3813

(Source: Chhattisgarh State Animal Husbandary Development Department)

पशुधन गणना रिपोर्टों के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि:

- देशी नस्ल की गायों की संख्या में कुछ हद तक कमी आई है।
 - संकर एवं उन्नत नस्लों की संख्या में वृद्धि हुई है।
 - भैंस पालन में स्थिरता बनी रही है।
 - बकरी एवं भेड़ पालन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
2. **दुग्ध उत्पादन में प्रवृत्तियाँ:** दुग्ध उत्पादन पशुधन उत्पादकता का प्रमुख संकेतक है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में रायपुर जिले में दुग्ध उत्पादन में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है।
3. **प्रति पशु औसत उत्पादकता का विश्लेषण**
- संकर नस्ल की गायों का औसत दुग्ध उत्पादन देशी नस्ल की तुलना में अधिक है।
 - संतुलित आहार एवं खनिज मिश्रण के उपयोग से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।
 - नियमित टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रमों से पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है।
4. **कृत्रिम गर्भाधान एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम**
- कृत्रिम गर्भाधान की वार्षिक संख्या में वृद्धि।
 - गर्भाधान सफलता दर में क्रमिक सुधार।
 - उन्नत नस्ल के बछड़ों का अनुपात बढ़ा।
5. **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभाव**
- खुरपका-मुंहपका एवं अन्य संक्रामक रोगों के मामलों में कमी आई है।
 - आपातकालीन उपचार सेवाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है।
 - स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जागरूकता बढ़ी है।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (पूर्व में रायपुर दुग्ध संघ) का पंजीयन क्रमांक 184 दिनांक 25.07.1983 है। संस्था का उद्देश्य सुदूर ग्रामीण अंचल की दुग्ध सहकारी समितियों से उचित दर पर दूध का संकलन करना तथा प्रसंस्करण पश्चात उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता युक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। महासंघ का गठन राज्य शासन द्वारा 30 जनवरी 2013 को किया गया है।

अधोसंरचना

1. दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र

क्र.	स्थान	प्रसंस्करण / प्रशीतन क्षमता (ली.)
01.	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला	1,00,000
02.	दुग्ध संयंत्र बिलासपुर	20,000
03.	दुग्ध संयंत्र जगदलपुर	10,000
04.	दुग्ध संयंत्र रायगढ़	10,000
05.	दुग्ध संयंत्र अम्बिकापुर	4,000
06.	दुग्ध शीत केन्द्र बसना	25,000
07.	दुग्ध शीत केन्द्र धमतरी	9,000
08.	दुग्ध शीत केन्द्र पखांजूर	15,000
09.	दुग्ध शीत केन्द्र भाठागांव	5,000
10.	दुग्ध शीत केन्द्र बेमेतरा	4,000
	योग (लीटर)	2,10,000

(Source: Statistics - Devbhog)

2. जिलावार बल्क मिल्क कूलर की जानकारी

क्र.	जिला	संख्या	कुल शीतलीकरण क्षमता (लीटर)
01.	रायपुर	5	6,500
02.	महासमुंद	22	42,000
03.	धमतरी	1	2,000
04.	बलौदाबाजार	6	4,500
05.	गरियाबंद	4	3,500
06.	बालोद	4	5,500
07.	खैरागढ़-छुईखदान	3	4,000
08.	बेमेतरा	4	5,500
09.	सारंगढ़	10	25,500
10.	जांजगीर-चांपा	3	6,000
11.	कांकेर	1	2,000
12.	कोण्डागांव	1	3,000
13.	मुंगेली	1	2,000
	योग	65	1,12,500

(Source: Statistics - Devbhog)

3. दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या

वर्ष	समितियों की संख्या
2017-18	820
2018-19	920
2019-20	984
2020-21	1,116
2021-22	1,095
2022-23 March	961

(Source: Statistics - Devbhog)

4. दुग्ध सहकारी समितियों में सदस्यों का अनुपातिक विवरण

क्रं.	विवरण	कुल सदस्य	
		संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य वर्ग	5,681	15.1
2.	अनुसूचित जाति	2,000	5.3
3.	अनुसूचित जनजाति	4,081	3.0
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	25,859	10.8
	योग	37,659	100.0
5.	महिला सदस्य	10,855	28.8

(Source: Statistics - Devbhog)

5. औसत दुग्ध संकलन प्रतिदिन

वर्ष	औसत दुग्ध संकलन प्रतिदिन (कि.ग्रा.)
2017-18	78600
2018-19	103070
2019-20	87260
2020-21	68431
2021-22	66118
2022-23	57200
2023-24	68668

(Source: District Wise DCS - Devbhog)

दुग्ध विपणन की दृष्टि से सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों से ज्ञात होता है कि:

- सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि हुई।
- संगठित दुग्ध संकलन केंद्रों का विस्तार हुआ।
- भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आई।

योजना लाभार्थियों की संख्या एवं प्रभाव

शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पशु वितरण, सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं ऋण सुविधा प्रदान की गई।

आँकड़ों के अनुसार:

- योजना लाभार्थियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि।
- महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी में वृद्धि।
- युवाओं द्वारा स्वरोजगार के रूप में पशुपालन अपनाने की प्रवृत्ति।

आय एवं लाभ में परिवर्तन का विश्लेषण

पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि का अंतिम उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना है। उपलब्ध आँकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि:

- नियमित दुग्ध विक्रय से मासिक आय में वृद्धि हुई।
- सहकारी समितियों से जुड़े पशुपालकों की आय अपेक्षाकृत अधिक पाई गई।
- बहुविध पशुपालन (गाय + बकरी + पोल्ट्री) अपनाने वाले परिवारों की आय अधिक स्थिर रही।

हालाँकि आय में वृद्धि का स्तर सभी वर्गों में समान नहीं है। सीमांत किसानों को पूंजी एवं संसाधन की कमी के कारण अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि पशुधन की कुल संख्या में अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई, किंतु नस्लीय गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। दुग्ध उत्पादन तथा प्रति पशु औसत उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी गई। दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित विपणन ने पशुपालकों को स्थिर एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराई। इससे नियमित आय सुनिश्चित हुई और लाभ में वृद्धि की संभावना बढ़ी। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। रोग नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों के कारण पशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है। यद्यपि योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए, परंतु सभी क्षेत्रों एवं वर्गों को समान लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सहकारी समितियों का विस्तार हुआ है, किंतु परिवहन एवं भंडारण सुविधाओं की कमी है।

सुझाव

अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

1. उन्नत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाया जाए।
2. चारा की मौसमी कमी को दूर करने के लिए चारा बैंक स्थापित किए जाएँ।
3. दूरस्थ ग्रामों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों संचालित की जाएँ। नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए।
4. पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों, पशु पोषण एवं प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण नियमित रूप से प्रदान किया जाए।
5. स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता एवं विपणन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
6. दुग्ध संग्रहण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए तथा कोल्ड चेन प्रणाली विकसित की जाए।
7. छोटे एवं सीमांत पशुपालकों के लिए सरल ऋण प्रक्रिया विकसित की जाए। जिला स्तर पर पशुधन से संबंधित अद्यतन आँकड़ों का डिजिटलीकरण किया जाए।

संदर्भ सूची

1. 20th Livestock Census Chhattisgarh State District-wise Livestock population 2019-20, https://agriportal.cg.nic.in/ahd/PDF_common/census20th/2_Districtwise_Animal_population_20th_LSC.pdf, Accessed on 10/01/2026.
2. Bardhan D.; Singh S.R.K.; Raut A.A.; Athare T.R. (2025) Livestock in Madhya Pradesh and Chhattisgarh: An Analysis for Some Policy Implications. *Agricultural Science Digest*, 45 (4), 729-735.
3. छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति, किसानों की बढ़ेगी आय, News 17feb 2025, <https://cmo.cg.gov.in/news/Dairy-development-in-Chhattisgarh-will-give-a-new-boost-to-the-rural-economy-and-increase-farmers'-income—Chief-Minister-Shri-Sai/U3VUOEsvaHZSckpRUGdSVDhaYTU1UT09>, Accessed on 18/01/2026.
4. Das Arghyadeep, et al (2020) Present Scenario and Role of Livestock Sector in Rural Economy of India: A Review. *International Journal of Livestock Research*, 10(11), 22-30, DOI:10.5455/ijlr.20200701051344
5. दुधारू पशु प्रदाय योजना krishak jagat 03 June 2025, <https://www.krishakjagat.org/news/chhattisgarh-government-started-milk-cattle-supply>, Accessed on 13/01/2026.
6. Economic survey of Chhattisgarh 2024-25, <https://descg.gov.in/Economic-Survey.aspx>, Accessed on 10/01/2026.
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021) *FAOSTAT statistical database*. <https://www.fao.org/faostat>, Accessed on 12/01/2026.
8. Gulati, Ashok & Juneja, Ritika (2022) Transforming Indian Agriculture. *Indian Agriculture Towards 2030*, 15 March 2022, Online ISBN 978-981-19-0763-0, http://DOI:10.1007/978-981-19-0763-0_2, Accessed on 09/01/2026.
9. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. “Manual of Trainer’s Training Programme for Skill and Entrepreneurship Development in Animal Husbandry”. July, 2013, Manual of Trainer’s Programme, Accessed on 14/01/2026.
10. Mishra, P.; Fatih, Chellai; Niranjan, H.K.; Tiwari, Shiwani; Devi, Monika; Dubey, Anurag (2020) Modelling and Forecasting of Milk Production in Chhattisgarh and India. *Indian Journal of Animal Research*, 54(7), 912-917.
11. National Dairy Development Board. (2022) *NDDDB annual report 2021–22*. <https://www.nddb.coop/information/stats>, Accessed on 12/01/2026.

12. National Statistical Office. (2022) *Statistical year book India.2022* Ministry of Statistics and Programme Implementation. <https://mospi.gov.in>, Accessed on 10/01/2026.
13. NITI Aayog (Nov. 2018) *Strategy for new India @75: Agriculture and allied sectors*. Government of India. https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/Strategy_for_New_India_0.pdf, Accessed on 11/01/2026.
14. prashasnik pratedan cg govt. 2010-11, https://agriportal.cg.nic.in/ahd/PDF_common/Prasasanik%20Prativedan%202010-11.pdf, Accessed on 12/01/2026.
15. Samridhi-YoJana 25 dec 2024, <https://dprcg.gov.in/post/1735142542/Raipur-Dairy-and-fisheries-cooperatives-launched-under-Samridhi-YoJana>, Accessed on 11/01/2026.
16. Sarkar Anupam (2020) Role of Livestock Farming in Meeting Livelihood Challenges of SC Cultivators in India. *Indian Journal of Human Development*, 14(1), <https://doi.org/10.1177/0973703020923863>, Accessed on 18/01/2026.
17. Tiwari, Pragma (2024) Contribution and Comparative Study of Devbhog in The Development of Milk Business. (With special reference to Chhattisgarh State Cooperative Milk Federation) *IJCRT* | 12(7), 115, ISSN: 2320-2882, <https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2407904.pdf>
